इमिलिहा में भाजपा नेता पर अवैध रेत उत्खनन का आरोप

पुलिस ने आपत्ति की तो घेरा थाना, भाजपा नेता ने थाना प्रभारी पर अभद्रता का लगाया आरोप

नवभारत न्यूज

पन्ना 16 नवंबर। कल रात मे पन्ना जिले के धरमपुर थाना अंतर्गत उस समय स्थिति विस्फोटक बन गई। जब भाजपा नेता सतानंद गौतम के भाई रामबाबू गौतम ने अपने सैंकड़ों समर्थकों के साथ थाने का घेराव कर दिया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे से थाना परिसर गूंज उठा।

सूचना पाते ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आसपास के थाना क्षेत्रों से काफी मात्रा मे पुलिस बल भेजा तब कहीं मामला किसी तरह से शांत हुआ। वहीं इस मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं जहां इमिलिया ग्राम के सैंकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर भाजपा नेता रामबाबू गौतम पर उनके गांव में अवैध रेत उत्खनन का आरोप लगाया है। वहीं रामबाबू गौतम ने जिला मुख्यालय मे प्रेस वार्ता कर थाना प्रभारी धरमपुर अनिल राजपूत पर सजातीय अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देने, रेत वाहनों से अवैध वसूली करने सहित अपने साथ थाने मे बुलाकर अभद्रता सहित कई गंभीर आरोप लगाये हैं। ग्राम इमिलिहा के सैंकड़ों ग्रामीणों ने एसपी पन्ना को दिये गये आवेदन मे उल्लेख किया है कि ग्राम इमिलिहा, पंचायत धरमपुर, थाना धरमपुर के निवासी हैं। हमारे गांव के पास स्थित नदी से रामबाबू गौतम एवं उसके साथी बीते समय से लगातार अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं। जब ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया तो उन्होंने गाली-गलौज कर डराने-धमकाने का प्रयास किया। गांव में गंभीर बात यह है कि जब थाना प्रभारी अनिल सिंह राजपूत जी ने स्वयं अवैध उत्खनन न करने और शांति बनाए रखने का निर्देश दिया, तब भी रामबाबू गौतम साथ आकर अनावश्यक तरीके से दबाव बनाने, झगड़ा करने व धमकाने की हरकतें करता है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो रही है। दिनांक 13 नवंबर को भी गांव में ट्रैक्टरों से अवैध भराई की जा रही थी और रोकने पर ग्रामीणों को धमकाया गया। और दिनांक 15 नवंबर को रात्रि लगभग 8.00 बजे अपने कुछ साथियों के साथ थाने में जाकर अनावश्यक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की। नदी में हो रहे अवैध उत्खनन को तुरंत रोका जाए, इस कार्य में शामिल व्यक्तियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

क्या कहते हैं भाजपा नेता

पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा नेता रामबाबू गौतम ने बताया कि थाना प्रभारी धरमपुर अनिल राजपूत द्वारा एक आरक्षक के माध्यम से फोन कर थाने बुलाया गया था। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझसे थाना प्रभारी ने कहा कि आपके द्वारा इमिलिहा में रेत का उत्खनन किया जा रहा है तो मैंने कहा कि मेरे द्वारा कोई अवैध उत्खनन नहीं किया जा रहा हैं आप कार्यवाही कर सकते हैं। इस पर थाना प्रभारी ने उनके साथ अभद्र भाषा एवं गाली गलौच करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रकरण दर्ज कर बंद कर दूंगा। सारी नेतागिरी भूल जाओगे। मैंने यह बात जाकर गांव में बताई, ग्रामीणों के साथ थाने के सामने प्रदर्शन किया गया। एसडीओपी सहित अपने भाई सतानंद गौतम को भी इसकी जानकारी दी। श्री गौतम ने कहा कि थाना प्रभारी राजपूत थाना क्षेत्र के कुछ सजातीय अपराधिक प्रवृति के लोगों को संरक्षण देते हैं और रेत वाहनों से अवैध वसूली करते हैं साथ ही कई गम्भीर आरोप थाना प्रभारी पर उनके द्वारा लगाये गये। और कहा कि यदि मैं दोषी हूं तो मेरे ऊपर कार्यवाही की जाये अन्यथा अभद्रता करने वाले थाना प्रभारी के ऊपर की जाये।

रामबाबू गौतम भाजपा नेता

क्या कहते हैं थाना प्रभारी

उपरोक्त मामले में थाना प्रभारी अनिल राजपूत का कहना है कि ग्राम इमिलिहा के ग्रामीणों की शिकायत पर उनके द्वारा रामबाबू गौतम को थाने बुलाया गया था और उन्हें रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने की समझाइश दी गई उनके द्वारा कोई भी अभद्रता नहीं की गई। फिर भी उनके द्वारा अनावश्यक रूप से अपने सैंकड़ों समर्थकों के साथ पुलिस पर दबाव बनाने के लिए थाने के सामने प्रदर्शन किया गया।

अनिल राजपूत थाना प्रभारी धरमपुर

सलेहा रेंज में 2.5 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाया

नवभारत न्यूज

पन्ना 16 नवंबर। आज दक्षिण पन्ना वनमण्डल के सलेहा परिक्षेत्र अंतर्गत सोनई बीट में लगभग 2.5 हेक्टेयर वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया।

वन विभाग की टीम ने पूरे क्षेत्र का पुनः सर्वे कर सीमांकन सुनिश्चित किया और वन सीमा को सही रूप में सुरक्षित किया। यह कार्रवाई रेंजर सलेहा जीतू सिंह बघेल के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र सहायक बालस्वरूप दहायत, दिलीप सिंह एवं बीट गार्ड बौलिया/सोनई विनय मिश्रा की सतत उपस्थिति एवं प्रयासों से सुबह से लेकर पूर्णता तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

विधायक पन्ना ने क्षेत्र के विकास कार्यों का किया लोकार्पण

नवभारत न्यूज

अजयगढ़/पन्ना 16 नवंबर

क्षेत्रीय विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह ने आज अजयगढ़ क्षेत्र का दौरा किया और यहां पर कई ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। क्षेत्रीय विधायक 12.00 बजे करीब अजयगढ़ से लगी हुई ग्राम पंचायत बहादुरगंज पहुंचे जहां पर उन्होंने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया जो सी आर एस मद से था जिसकी लागत करीब 10 लख रुपए थी उन्होंने बहादुरगंज से तहसील कार्यालय को जोड़ने वाले मार्ग में सीसी रोड का भी भूमि पूजन किया। विधायक ने अपने उद्बोधन में कहा कि बहादुरगंज से तहसील कार्यालय जोड़ने के लिए लगभग 10 लख रुपए की सीसी सड़क बनाई जा रही है जो ग्रामीणों को भारी दिक्कत होती थी और कई बार मुझसे ग्रामीणों द्वारा माग की गई थी की तहसील कार्यालय को जोड़ने वाला मार्ग बनवाया जाए। विधायक का काफिला आगे बढ़ा कुंवरपुर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का लोकार्पण किया जिसकी लागत लगभग 47 लाख रुपए थी कुंवरपुर में नया पंचायत भवन सर्व सुविधायुक्त बनाया गया है। विधायक द्वारा सव्दुआ में भी सामुदायिक भवन सात लाख एवं सामुदायिक भवन आदिवासी मोहल्ला में बनवाया गया जिसकी लागत पांच लाख का लोकार्पण किया गया। ग्राम पंचायत पड़रहा में भी सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया सभी जगह विधायक का जोरदार स्वागत किया गया। उक्त कार्यक्रम में विधायक के साथ नगर परिषद अध्यक्ष सीता सरोज गुप्ता तहसीलदार सुरेंद्र कुमार, संजय सुल्लेरे, रवि रावत, अवध तिवारी सुरेश यादव सहित अधिकारी कर्मचारी भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता उनके साथ रहे।

सागौन लकड़ी तस्कर के ठिकाने पर वन विभाग टीम का छापा

नवभारत न्यूज

पन्ना 16 नवंबर। दक्षिण पन्ना वनमंडल द्वारा 16 नवंबर को वन अपराध के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कार्रवाई की गई। वन विभाग को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मोहाई में निवासी रामप्रसाद उर्फ पप्पू बेड़िया अपने घर में अवैध सागौन लकड़ी का संग्रह कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने तत्काल एक विशेष टीम गठित की और त्वरित दबिश की योजना तैयार की।

संयुक्त टीम द्वारा की गई छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से लगभग 2 घनमीटर अवैध सागौन लकड़ी बरामद की गई। उक्त लकड़ी को जब्त कर वन अमले के कब्जे में ले लिया गया। फरार आरोपी की तलाश वन विभाग द्वारा की जा रही है। यह सफल कार्यवाही मोहन्द्रा वन परिक्षेत्र अधिकारी अभय दुबे के नेतृत्व में पवई एवं मोहन्द्रा रेंज की संयुक्त टीम द्वारा की गई। प्राप्त सामग्री एवं साक्ष्यों के आधार पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33 के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की जांच प्रारंभ कर दी गई है। दक्षिण पन्ना वनमंडल द्वारा आरोपी पप्पू बेड़िया की सटीक जानकारी उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति के लिए 5000 रूपये के ईनाम की घोषणा की गई है।

शिक्षा विभाग में आकस्मिक व स्पोर्टस निधि में घोटाला की संभावना

निष्पक्ष जांच से हो सकता है खुलासा

नवभारत न्यूज

पन्ना 16 नवंबर। जिले में शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक पाठशाला एवं माध्यमिक शाला में छात्रों को खेलने के लिए खेलकूद सामग्री के लिए शासन द्वारा राशि प्रदाय की जाती है, इसी तरह हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल में खेल सामग्री एवं आकस्मिक निधि प्रदाय की जाती है।

हर वर्ष माध्यमिक सहित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में सीधे खातों में राशि भेजी जाती है लेकिन सन 2021-22 के सत्र में शासन द्वारा नियम बदले गए जिसके अनुसार विद्यालयों के खातों में सीधे उक्त राशि न भेजकर प्राथमिक एंव माध्यमिक शालाओं की राशि बीआरसी के माध्यम से विद्यालयों में राशि जाना था इसी तरह हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी की राशि सीधे जिला शिक्षा कार्यालय भेजी गई लेकिन स्थिति जिले की यह है कि 80 फीसदी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में न तो खेलकूद सामग्री की खरीदी की गई और न ही आकस्मिक व्यय में खर्च किए जाने वाले विद्यालयों में कोई काम कराए गए, कुछ विद्यालयों के द्वारा पन्ना, गुनौर, पवई, शाहनगर अजयगढ़ क्षेत्र के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों द्वारा बिल तो लगाए गए लेकिन उनकी राशि का भुगतान नहीं हुआ। हासिल जानकारी के अनुसार पता चला है कि स्पोर्ट एवं आकस्मिक निधि प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं को जो मिलती थी इस साल अभी तक उसमें कोई भी प्रगति नहीं हुई तथा शिक्षा विभाग के भिन्न भिन्न पदों में बैठे हुए अधिकारियों द्वारा अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। सभी के लिए खेल कूद सामग्री जिसमें प्राथमिक के लिए 5 हजार, माध्यमिक शालाओ के लिए 10 हजार तथा हाई स्कूल के लिए 20 हजार वं हायर सेकण्डरी के लिए 30 हजार के लगभग राशि आई थी, प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं की स्पोर्टस की सामग्री के लिए लगभग 1 करोड 80 लाख रूपये आए थे, इसी तरह आकस्मिक निधि के भी 10 हजार से लेकर हायर सेकण्डरी स्कूल तक में 50 हजार रूपये की राशि आई थी, यह आकस्मिक निधि लगभग 4 करोड के लगभग होती है इस संपूर्ण राशि में 2021-22 सत्र के बजट में काफी घपला मचा हुआ है, कुछ चर्चाएं यह आ रही हैं कि शासन द्वारा इस बार पिछले वर्षो की अपेक्षा इस संबंध में नियम बदल दिए गए है।

इस संपूर्ण क्रिया कलाप में जो अधिकारी हैं वह सभी मौन हैं तथा इस संबंध में उनके द्वारा साल भर मॉनीटरिंग नहीं की गई, बरह हाल मामला चाहे जो भी हो लेकिन शासन से आई हुई राशि में काफी कुछ अनियमितताएं व घपला, घोटाला नजर आ रहा है जिसके लिए प्रशासन को जांच करनी चाहिए।

अपडेट नहीं की जा रही जानकारी, शोपीस बनकर रह गया एजुकेशन पोर्टल

नवभारत न्यूज

पन्ना 16 नवंबर। राज्य शिक्षा केन्द्र का एजुकेशन पोर्टल 2.0 अब कचरा घर जैसा बन चुका है। जबसे एजुकेशन पोर्टल 3.0 लागू किया गया है जब से पोर्टल 2.0 को ऐसा लगता है जैसे उसे वेन्टीलेटर में डाल दिया गया हो। कोई आदेश, निर्देश अब इस पोर्टल में अपलोड नही होते। कई महीनो तक पोर्टल को अपडेट ही नहीं किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित योजनाओं की अद्यतन स्थितियों को भी अपडेट नही किया जाता।

लिहाजा इससे समझा जा सकता है कि एजुकेशन पोर्टल 2.0 को एक औपचारिक एवं प्रतीकात्मक पोर्टल मान लिया गया है। इसके आम नागरिकों को पोर्टल के माध्यम से अद्यतन कोई भी जानकारी अब नहीं मिल सकती।

पोर्टल 3.0 का उपयोग केवल विभागीय, नागरिकों के लिये नही:- एजुकेशन पोर्टल 3.0 का उपयोग या तो विभाग कर सकता है अथवा विभागीय कर्मचारी अथवा अपनी आवश्यकता के अनुसार संबंधित मान्यता प्राप्त स्कूल का संचालक। जबकि सामान्य व्यक्ति इस पोर्टल को न तो खोल सकता और न ही उसे देख सकता। उसके अंदर जो डाटा रखा जाता है उसे गोपनीय बना दिया गया है। इसलिये इसका उपयोग जनता के लिये उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों को जहां एक पोर्टल में छिपाया जा रहा है गोपनीय रखा जा रहा है वही दूसरे पोर्टल को अपडेट ही नहीं किया जा रहा है। तब सवाल यह उठता है कि आखिर आनलाईन युग में सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों की जानकारी कैसे मिल सकती है। आखिर सूचनाओं को छिपाने की कोशिश क्यों की जा रही है ? इस संबंध में न तो कोई सक्षम एजेंसी यह जानने का प्रयास कर रही है और न ही कोई कार्रवाई हो रही है। जबकि सरकारी विभाग कोई भी विभागीय पोर्टल का निर्माण करता है तो करोड़ो रूपये इसलिये खर्च करता है कि विभागीय गतिविधियों की जानकारी अपडेट की जायेगी। उसे जनका भी देखने के लिये उपलब्ध करवाया जायेगा। यहां तक कि सूचना अधिकार अधिनियम में भी इस बात का प्रावधान किया गया है।

सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है : कनौजिया

नवभारत न्यूज

पन्ना 16 नवंबर। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित पन्ना मे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मे 72वां अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह अंतर्गत दिनांक 16 नवंबर को इफको के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमे जिले की सभी पैक्स के समिति प्रबंधक, शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम इफको के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेष मौर्या के द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा एवं सहकारिता पर विस्तार से बताया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ0 पी.एन.त्रिपाठी एवं डॉ0 आर.के. जयसवाल के द्वारा खाद का बेहतर इस्तेमाल की जानकारी दी गई, फसलों के रोग एवं उपचार के बारे मे विस्तार से बताया गया। बैंक के मुख्यकार्यपालन अधिकारी एस.के. कनौजिया द्वारा सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाना एवं केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सहकार से समृद्धि के बारे मे जानकारी दी गई। सभी पैक्स के समिति प्रबंधकों को नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, सागरिका खाद के वितरण बढ़ाये एवं प्रचार-प्रसार करने हेतु कहा गया। कार्यक्रम मे सर्वाधिक नेनो डीएपी, नेनो यूरिया, सागरिका वितरण करने वाली 3 सिमतियां रैपुरा, बृजपुर एवं बगरौड़ के समिति प्रबंधकों को प्रषस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम मे एस.एल. धुर्वे जिला विपणन अधिकारी मार्कफेड, डॉ0 रीतेष बगौरा वैज्ञानिक, अमित श्रीवास्तव विपणन अधिकारी सहकारी बैंक, राजेन्द्र मिश्रा शाखा प्रबंधक सहित सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधक एवं समिति प्रबंधक उपस्थित रहे।

यह कैसी हितैषी सरकार जहां एक माह से डीएपी के लिए तरस रहे किसान, पक्ष विपक्ष मौंन

नवभारत न्यूज

पन्ना 16 नवंबर। रवि फसल की बुआई के लिए लगभग एक माह से डीएपी खाद का संकट चल रहा है। किसान महंगे दामों पर लोकल कम्पनी की डीएपी खरीदने को मजबूर हैं। जिले की समितियों सहित एवं जिला मुख्यालय सहित डीएपी गायब है। किसान हितैषी सरकार ने किसानों की यह दुर्दशा है और जिले के नेता एवं जनप्रतिनिधि एवं नेता मौंन हैं।

बाजार से डीएपी गायब

बाजार में खाद तो उपलब्ध है किन्तु डीएपी का अता-पता नहीं है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि व्यापारियों को प्राप्त होने वाली डीएपी आखिर कहां चली गई? कही ऐसा तो नही है कि डीएपी का उठाव करके व्यापारी उसे संकट के समय महगे दामों में बिक्री करने के लिये पहले से ही रख लिये हों। जबकि उसके पहले वे डीएपी का संकट बताकर अन्य वेरायटी की उर्वरक की बिक्री कर रहे हों। इसलिये प्रशासन को इस बात की जांच करनी चाहिये कि व्यापारियों को प्राप्त होने वाली डीएपी का यदि उठाव हुआ है तो वह बिक चुकी है अथवा उसे जमाखोरी करने के लिये रख लिया गया है। चूंकि व्यापारी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जब यूरिया का सकट होता है और किसान को आवश्यकता होती है तो वह किसी भी भाव खरीदने के लिये तैयार हो जाता है।

जैसे ही धान की कटाई पूरी हो जाती तो किसानो को न केवल पानी और खाद की आवश्यकता होगी। वहीं पानी के लिये बिजली की मांग होगी तो बोनी के लिये डीएपी की। अभी धान की कटाई चल रही है किन्तु जैसे ही हार्वेस्टिंग का समय पूरा हो जायेगा तो बोनी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जायेगी। इसलिये जाने वाला पखवाड़ा बिजली और खाद के लिये महत्वपूर्ण होगा।

समितियों में चल रहा कालाबाजारी जैसा हाल:- सहकारी समितियों में कालाबाजारी जैसी स्थिति है। कई किसानों को अभी तक परमिट के लिये भटकाया जा रहा है तो खास एवं प्रभावशाली लोगों को परमिट भी जारी हो जाता हे एवं स्टाक होने पर खाद भी मिल जाती है। जबकि सामान्य किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। किन्तु इस स्थिति को देखने परखने के लिये अभी प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ज्ञात हो कि समितियों के माध्यम से किसानों को कर्ज पर खाद उपलब्ध करवाई जाती है। जहां कर्ज की अदायगी फसल पकने के बाद करनी होती है। लिहाजा प्राथमिकता सूची के आधार पर खाद का वितरण होना चाहिये। किन्तु समितियों में ऐसा नही होता बल्कि वहां जिम्मेदार व्यक्ति जिसे चाहता है उसे पहले देता है और जिस नहीं चाहता उसे बाद में अथवा लटकाये रहता है।

गुणवत्ता जांच के लिये टीमें गठित किन्तु कार्रवाई शून्य:- ज्ञात हो कि खाद व बीज की गुणवत्ता जांच के लिये टीमों का गठन तो किया जा चुका का है ताकि बोनी के पूर्व भण्डारित खाद व बीज की जांच की जा सके और सेम्पल लिये जा सकें। किन्तु जिन टीमों को अभी तक तक में कार्रवाई प्रारंभ कर देनी चाहिये उनका कहीं अता पता नहीं है। गुणवत्ता की जांच करने वाली जिला स्तरीय टीमों की सक्रियता अभी दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक यही पता नहीं है कि गुणवत्ता जांच के लिये कोई रोस्टर कृषि विभाग ने तैयार किया है। ताकि बड़े व्यापारियों से लेकर शहरी एवं कस्बाई एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वैध व अवैध कारोबारियों को कवर किया जा सके। लिहाजा प्रतिवर्ष की भांति जांच टीमें औपचारिकता ही कर सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो मानक के अनुसार खाद एवं बीज की जांच समय पर नही हो सकती।

जमीन आवंटन के 10 साल बाद भी नवीन बस स्टैंड का काम ही शुरू नहीं

नवभारत न्यूज

पन्ना 16 नवंबर। नगर के प्राणनाथ बस स्टैंड से जितनी बसों का संचालन होता है, उसके अनुसार उन्हें खड़ा करने का स्थान ही पर्याप्त नहीं है। बस चालक आड़ी-तिरछी बसें खड़ी करते हैं। इससे बस स्टैंड में अव्यवस्था फैलने के साथ ही यात्रियों को भी परेशानी क सामना करना पड़ रहा है।

इस समस्या को देखते हुए दस साल पहले कमला बाई ताल के नजदीक नया बस स्टैंड बनाने के लिए जमीन आबंटित की गई थी तब नये बस स्टैंड तक आने-जाने के लिए सीसी रोड भी बनवाई गई। 10 साल बाद भी नये स्थान को बस स्टैंड के रूप में विकसित नहीं किया जा सका है। इससे बस स्टैंड स्थनांतरित नहीं हो पाया है। लोगों को आज भी समस्याओं का सामना करन पड़ रहा है। प्राणनाथ बस स्टैंड से प्रतिदिन करीब 300 बसों का यहां से संचालन होता है। उनके लिए परिसर में मात्र एक दर्जन ही प्लेटफार्म हैं स्थान छोटा पडने के कारण रात को हाल्ट करने वाली बसों के चालक वाहनों को पेट्रोल पंपों में ले जाकर खड़ा करते हैं। वहीं कुछ परिचालक द्वारा बस स्टैंड में वाहनों को पूरी रात के लिए खड़ा कर दिया जाता है। इससे सुबह यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन बसों को हटाने के नाम पर कार्रवाई हर बार सिर्फ नोटिस तक सीमित रही है।

ऑटो, ई-रिक्शा भी बने परेशानी:- बसों के आते ही ऑटो चालकों की धमाचैकड़ी भी यात्रियों और बस संचालकों की परेशानी बनी हुई है। ऑटो चालक बसों के गेट से प्रवेश करते ही सवारियों के लिए चारों ओर से घेर लेते हैं। बस स्टैंड से जबलपुर, रीवा, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, सतना, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, झांसी, सीधी सहित अन्य बड़े शहरों को बसों का संचालन होता है। इसके अलावा स्थानीय रूटों में अजयगढ़, पवई, गुनौर, मोहन्द्रा, सिमरिया, सलेहा, ककरहटी, रैपुरा, सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को बसों की सुविधा है।

बसों यात्रियों की संख्या बढ़ी, स्टैंड जस का तस:- रेल सुविधा विहीन पन्ना शहर से आवागमन का एकमात्र साधन बसें ही हैं। यही कारण है कि बीते दस साल में बसों और यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। प्राणनाथ बस स्टैंड से 300 बसों में रोजाना 8 से 10 हजार यात्री सफर करते हैं। यात्रियों समेत बस चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमेशा हादसे का भी डर बना रहता है।

जाम से भी लोग परेशान- बस स्टैंड शहर के बीचोबीच स्थित है, ऐसे शहर के अंदर से बसें गुजरती हैं। इससे रोजाना जाम के हालात बने रहते हैं। लोगों को रोजाना इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके शहर के यातायात को सुगम बनाने में बाधक बन रहे बस स्टैंड को शिफ्ट करने के प्रयास तक नहीं किए जा रहे है।

1 करोड़ खर्च करने के बाद भूले जिम्मेदार:- शहर के बीचोबीच स्थित बस स्टैंड को कमलाबाई तालाब के पास शिफ्ट करना प्रस्तावित किया गया था। जिसके लिए बीआरजीएफ मद से 1 करोड़ रुपए की लागत से बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए सीसी रोड और नालियों का निर्माण कराया गया था।

1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जिम्मेदार प्रस्तावित बस स्टैंड को भूल गए हैं।